10 मार्च तिब्बती जनक्रान्ति के 60वीं वर्षगांठ पर तिब्बती संसद के अभिभाषण।

तिब्बती जनता द्वारा चीन के शासकों के प्रति अहिंसक जनक्रान्ति के साठ वर्ष के उपलक्ष्य में 10 मार्च 2019 यह एक विशिष्ट दिवस के रूप में माना जाता है।

01 अक्टूबर 1949 के दिन चीनी साम्यवादी शासकों ने चीनी लोक गणराज्य की स्थापना की। इसके उपरान्त उन्होंने तिब्बत को मुक्ति दिलाने के दिखावे पर तिब्बत के भीतर अतिक्रमण करते हुये समस्त तिब्बत को अपने आधीन में कर लिये। इस घटना से अगले नौ वर्ष तक तिब्बती सरकार और परम पावन चौदाहवें दलाई लामा जी ने चीन के साम्यवादी शासन के साथ इस समस्या के हल के लिये हर सम्भव प्रयास किये। जब कि दूसरी तरफ परम पावन और तिब्बती सरकार के बिना किसी जानकारी के चीनी शासकों ने यहाँ तक कि ङापोद् नावाङ् जिगमे की अध्यक्षता वाले तिब्बती सरकार की शान्ति वार्ता प्रतिनिधि मण्डल पर असंवैधानिक तरीके से बलपूर्वक सत्रह सूत्रीय समझौते पर 23 मई 1951 को हस्ताक्षरित किये गये। सत्रह सूत्रीय समझौता की अपेक्षित उपदेश के अनुकूल तिब्बती सरकार के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा चीन सरकार के साथ वार्ता सफल होने पर अधिकाधिक प्रयास विफल रहा क्योंकि यह समझौता केवल चीनी साम्यवादी शासन के हितों को सर्वोपरि रखा गया था। यहाँ तक कि तिब्बती सरकार को सार्वजानिक स्तर पर इस समझौता को समर्थन करने का निर्देश जारी किया गया, जिसके फलस्वरूप तिब्बती शान्ति वार्ता प्रतिनिधि मण्डल को 24 से 26 सितम्बर 1951 में तथाकथित सत्रह सूत्रीय समझौता को जारी किया गया।

इस सन्धि के प्राराम्भिक चरण में तिब्बती सरकार के द्वारा तीन शर्त रखे गये थे जिस पर चीनी साम्यवादी शासन यदि अमल करते हैं तब तिब्बती सरकार इस सत्रह सूत्रीय समझौते के लिये बाध्य रहेगा। इस पर चीनी के ओर से समस्त तिब्बती भूभाग को एकीकृत करने हेतु स्हिठोन,

कनसु, युनन, छ्होडोन इत्यादि क्षेत्र में रहने वाले तिब्बती लोगों से मन्त्रणा करने के पश्चात् उस पर अमल किये जाने की बात कही। इसके बाद चीनी शासक ने बीस हज़ार से अधिक चीनी सैनिकों को तिब्बत के माध्य क्षेत्र में भेज कर एक के बाद एक समस्त तिब्बती क्षेत्र को अपने कब्ज़े में कर लिया। दूसरी ओर तिब्बत में नरसंहार जैसे स्थिती के बचाव में परम पावन दलाई लामा जी ने विवश्तापूर्वक सत्रह सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करवाये गये। तिब्बत में चीनी सैनिकों की बढ़ते हलात को देखते हुये तिब्बती घरों से उनके जीविका के लिये भोजन प्रबन्ध करने का आदेश दिये गये। इतना ही नहीं भोजन सामग्री के दरों में दस फीसदी तक बढ़ोतरी करते हुये तिब्बती लोगों की जीविका पर बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। इन्हीं परिस्थियों के चलते तिब्बती लोगों में विरोध के असार उत्पन्न होने लगे जब कि चीनी सरकार स्थिति से निपटने के लिये तिब्बती सरकार और परम पावन दलाई लामा जी के आधिपत्य पर ओर अधिक हस्ताक्षेप करने लगे। अम्दो ओर खम क्षेत्र में तिब्बती लोगों की जीवका पर अमानवीय तरीके से विस्थापित किये गये। सांस्कृतिक केन्द्रों को नष्ट किये गये, असंख्य तिब्बती लोगों के नरसंहार किये गये और बहुत से बन्दी बनाये गये लोगों की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुये। जिस प्रकार से तिब्बती लोगों पर अत्याचार बढ़ते गये उसी के कारण अन्ततः 10 मार्च 1959 के दिन तिब्बत के राजधानी ल्हासा में समस्त तिब्बती लोगों ने जन विद्रोह किये। उस दिन चीनी शासक ने बहुत से तिब्बती लोगों के हत्यायें, बन्दी और दण्डित इत्यादि करवाये गये जिससे मानों कि मनुष्य लोक को नर्क लोक बना दिया गया हो। इसी दर्दनाक परिस्थिति के चलते आज 60 वर्ष पूरे हुये हैं। इसी उपलक्ष्य में समस्त तिब्बती के वह सभी महान् पुरुष व महिलायें जिन्होंने अपने देश और संस्कृति के लिये जो आहुति दी है उनके प्रति सभी तिब्बती लोगों के ओर से श्रद्धांजली अर्पित करते हैं साथ ही वर्तमान में भी तिब्बत के भीतर रह रहे चीनी शासकों के जुल्म सहने वालों के साथ हमारे संवेदनायें भी हैं।

सन् 1959 से लेकर गत् साठ वर्षों में चीनी शासकों के अतिक्रमण फलस्वरूप लाखों तिब्बती लोगों की हत्याये हुये हैं। न केवल तिब्बती भूमण्डलीकरण का सर्वनाश हुआ है अपितु 1956 में लोकतान्त्रिक प्राणाली में हस्ताक्षेप, 1968 में सांस्कृतिक विध्वंस और 1979 से लेकर 1985 तक आर्थिक पतन, 1986 से लेकर 1991 तक तिब्बत पर सुनियोजित तरीके से चीनी भूभाग में अधिकृत करने हेतु सातवीं पाँच वर्षीय योजना के अन्तर्गत तिब्बती मठों का विध्वंस, तिब्बत के भीतर आन्तरिक युद्ध करवा कर एक दूसरे के हत्यायें करवाना, 1968 से लेकर 1973 तक

आकाल के कारण तीन सौ चालिस हज़ार से अधिक लोगों के मरने की स्थिति उत्पन्न होना, तिब्बती पर्यावरण के साथ असीमित दोहन कराया जाना, असंख्य चीनी लोगों को तिब्बत में बसा कर चीनी बाहुल्य संख्या में परिवर्तित किया जाना इत्यादि विभिन्न रूप से तिब्बती लोगों के अस्मिता पर प्रहार करने का प्रयास किया गया फिर भी समस्त तीनों प्रान्त के तिब्बती लोगों ने दृढ़ता और मनोबल का अद्‌वितिया परिचय देते हुये तिब्बत के धर्म एवं संस्कृति, भाषा इत्यादि के संरक्षण में चीन के स्वार्थ नीति का अनेकों अनेक विरोध किये हैं।

सन् 1987 से तिब्बत के राजधानी ल्हासा में जब तिब्बतियों द्‌वारा शान्तिपूर्ण तरीके से चीन के हिंसक शासन का विरोध किये गये तब असंख्य तिब्बती लोगों को बन्दी बनाकर उनके साथ सख्ती की गयी। इसके बाद मार्च 1989 में ल्हासा में हिंसकपूर्वक स्थिति को सख्त की गयी। उसी प्रकार सन् 2008 में भी समस्त तिब्बती लोगों ने चीन के क्रूरतापूर्ण नीतियों का विरोध किया जिसमें अनगिनत तिब्बती मारे गये, घायल हुये, आर्थिक दण्ड दिया गया और उसी प्रकार बहुत से लोगों को बन्दी बनायां गया। चीन द्‌वारा निरन्तर अपने क्रूरतापूर्ण नीतियों का मूल्यांकान करने के बजाय और इन्हें सख्ती से लागू करने की फलस्वरूप 2009 से अब तक तिब्बत में 153 साहसिक तिब्बती देशप्रमियों ने आत्मदाह किये हैं। जिसमें 22 लोगों के घायल होने तथा उनके विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। और दूसरी ओर 131 लोग शहीद हुये हैं। अर्थात् इन 60 वर्षों में तिब्बती जनमानस पर स्वतः चलने की, रहने की और व्यवहार करने की मूलभूत मानवीय मूल्यों का जिस तरह हनन हुआ है वह निरन्तर चल रहा है।

दूसरी ओर 31 मार्च 1959 को भारत में परम पावन दलाई लामा जी आगमान के इन 60 सालों के अन्तराल में तिब्बत के भूभाग के संरक्षण के दूरगामी दृष्टि रखते हुये सर्वथा चीनी शासकों के साथ अहिंसक तरीके से समायोजन में लगे रहे। तिब्बती के संस्कृति के संरक्षण, तिब्बती पहचान की सुरक्षा हेतु निष्कासन में तिब्बती लोकतन्त्र के तीन स्तम्भों का स्थापना, तिब्बती शारणर्थी निवास, बौद्‌ध मठों, शिक्षा और सांस्कृतिक केन्द्रों के स्थापना इत्यादि कार्यकलापों से तिब्बत के सभ्यता को और अधिक जीवन प्राप्त हुये हैं। इस योगदान से तिब्बती के संघर्ष का न केवल सत्यपीत होगा अपितु तिब्बती जनमानस के पहचान भी सुरक्षित रख पाने की भूमिका आदा कर सकती है।

सन् 1974 से लेकर परम पावन दलाई लामा जी सर्वथा तिब्बत और चीन के द्विपक्षीय संघर्ष का संवाद से ही हल होने के पक्षधर रहे हैं। इसी श्रृंखला में 1979 में जब चीन के नेता तेङशो फिङ ने तिब्बत के मुद्दे पर जब उन्होंने स्वतन्त्रता के अतिरिक्त किसी भी मुद्दे पर वार्ता की सम्भावनाओं के संकेत दिये, तब तिब्बती और चीन के दूरगामी रिश्तों को ध्यान में रखते हुये मध्यम मार्ग का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन चीन शासकों द्वारा तिब्बत के स्थिति का हल ढूंढने के बजाय इस विषय को परम पावन के व्यक्तिगत विषय का हवाला देते हुये अकारण सार्थक नतीजों से दूर भागते रहे। 1977 में तिब्बत और चीन के बीच इस मद्दे के हल खोजने हेतु अमरेकी संसद के मानवाधिकार आयोग में पाँच सूत्रीय प्रस्ताव रखे गये थे। उसके उपरान्त 1988 में फ्रांस स्ट्रेसबक शहर में यूरोपिय संसद के तत्वाधान में उल्लेख प्रस्ताव पर विस्तारपूर्वक सम्भाषण हुये। मध्यम मार्ग नीति को निष्कासित तिब्बती संसद में 18 सितम्बर 1997 को सर्वसम्मति से पारित किये गये थे। इसी नीति का अनुपालन करते हुये सन् 2002 से 2010 तक परम पावन दलाई लामा के प्रतिनिधि और चीन सरकार के प्रतिनिधि के बीच नौ बार द्विपक्षीय वार्ता हुयी और एक आन्तरिक चर्चा हुये हैं। हालाँकि 2010 से चीन सरकार के तरफ से वार्ता को निरन्तर रखने में कोई इच्छा ज़ाहिर नहीं की है फिर भी परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बती प्रशासन अपने तरफ से इस संवाद की निरन्तरता की अपेक्षा रखते हैं। साथ ही तिब्बत और चीन के समस्या का हल मात्र संवाद से ही सम्भव होगा इस विश्वास को पुनः बल देते हैं। तिब्बत के सत्यग्राह के प्रति अमेरिका, यूरोप, विशेषरूप से भारत और अन्य देशों के सरकार, संसद, गैर-सरकारी संस्थायें, तिब्बत समर्थक संघगठन, अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय एवं व्यक्तिगत इत्यादि बहुत लोगों से प्रशंसा और समर्थन प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही विदेशों में रह रहें चीनी नागरिकों में विशेषकर जो बुद्धिजीवियों और लोकतन्त्र के समर्थक, उसी प्रकार से चीन में रहने वाले कुछ आमुख बुद्धिजीवियों द्वारा भी समर्थक प्राप्त हो रहा है। इसी तरह विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र एवं अनेक देशों के संसदों में तिब्बत पर प्रस्ताव पारित हुये हैं। इसी प्रकार तिब्बत के भीतर वस्तुस्थिति को जान पाने के दृष्टि से तिब्बत में आवागमन का विधेयक (The Reciprocal Access to Tibet Act) को 11 दिस्मबर 2018 में अमरेकी संसद के अपर हॉवस में पारित किया गया जिस पर 19 दिस्मबर 2018 को अमरेकी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित होने से इसे स्वीकृत किया गया। इस विधेयक के पारित होने से तिब्बत के भीतरी हालात को विश्व पटल पर जानने की सम्भावनायें बढ़ने की अपेक्षा करते हैं।

गत् 60 वर्षों के आन्तराल में चीनी शासकों द्वारा तिब्बत के भूभाग पर जिस प्रकार के नीतियों के लागू से तिब्बत को विश्व के मानचित्र से हटाने का जो भरसक प्रयास हो रहा है इसके बवाजूद तिब्बत के भीतर – बाहर रह रहे समस्त तिब्बती लोगों के ओर से तिब्बत के मुक्ति साधना, तिब्बती जनमानस की पहचान, भाषा, संस्कृति, परम्परा इत्यादि मूल्यों का जिस प्रकार से हम संरक्षित रखने में सफल हुये हैं यह हमारे लिये एक विशेष उपलब्धी से कम नहीं है। सपष्ट रूप से इसका श्रेय परम पावन दलाई लामा जी और वरिष्ठ तिब्बती पीढ़ी के निस्वार्थ उन बुद्धिजीवियों के पृथक प्रयासों के चलते हमें यह उपलब्धी प्राप्त हुये है जिसके प्रति आज इस अवसर पर कृतज्ञता अर्पित करते हैं।

जिस प्रकार भाषा मानव जाति का जिर्णोद्धार है उसी प्रकार तिब्बत के संघर्ष का मार्ग अहिंसा से ही प्राप्त होगा। इसी क्रम में परम पावन दलाई लामा के उपदेशों को ध्यान में रखते हुये विशेषरूप से तिब्बती मानवजाति के पहचान, भाषा, संस्कृति इत्यादि इन मूल्यों का संरक्षण एवं संवर्धन तिब्बती प्रशासन, बौद्ध मंठ, विद्यालय, सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थायें, विभिन्न तिब्बती बस्तियों में भिक्षु-भिक्षुणी, छात्रों, लोगों और विशेषरूप से पदाधिकारियों से हम यह प्रार्थना करना चाहेंगे कि तिब्बत के संघर्ष का सत्यपित होने तक हम सभी को दृढ़तापूर्वक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में कोई चूक न हो।

इसी प्रकरण में, विशेषकर भारत सरकार और तिब्बत समर्थक अन्य देशों के सरकार, संसद, संघठन, बुद्धिजीवी, पत्रकार, जनता, छात्र, चीनी नागरिकों के प्रति निरन्तर निष्पक्ष प्राप्त हुये समर्थन के लिये आज इस अवसर पर आभार प्रकट करते हैं।

अन्ततः परम पावन दलाई लामा जी के न केवल दीर्घायु के कामना करते हैं अपितु उनके हर कार्य के मंगलकामना करने के साथ, तिब्बत मुक्ति साधना के शीघ्र-अतिशीघ्र सफल होने की कामना करते हैं।

तिब्बती जन संसद
10-03-2019

. . . . . .

** In case of any discrepancy between this Hindi translation and its Tibetan original, the latter should be considered as authoritative and final for all purposes.*